शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 48 वां वर्ष

ई-पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 48 अंक-45 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 13-20 नवम्बर 2023 मूल्य पांच रूपये

डी.जी.पी. प्रकरण में सरकार की निष्पक्षता लगी दाव पर

शिमला/शैल। क्या किसी को प्रदेश के डी.जी.पी. के हाथों या उसके माध्यम से अपनी जान और माल का खतरा हो सकता है? क्या ऐसी शिकायत को डी.जी.पी. अपने ही स्तर पर झूठ का पुलिन्दा कहकर शिकायतकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करवा सकता है? क्या ऐसी शिकायत पर अदालत के दखल पर भी पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करके अपने निष्पक्ष होने का दावा कर सकती है? क्या डी.जी.पी. के खिलाफ शिकायत आने पर भी सरकार उसी तंत्र पर भरोसा करके एक निष्पक्ष जांच हो पाने का दावा कर सकती है? यह और ऐसे ही कई सवाल निशान्त द्वारा प्रदेश के डी.जी.पी. के खिलाफ एस.पी. शिमला को भेजी शिकायत के बाद उठ खड़े हुए हैं। क्योंकि जान और माल का ही खतरा हो जाने से बड़ा कोई आरोप नहीं हो सकता। जो भाजपा नेतृत्व प्रदेश की बिगड़ती कानून और व्यवस्था पर लगातार सरकार पर हमलावर होता रहा है वह ऐसे आरोपों पर मौन साध ले तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। आज पूरे प्रदेश की नजरें इस प्रकरण पर लग गयी है। इसलिये इस पर चर्चा करना आवश्यक हो जाता है।

एस.पी. शिमला को संबोधित और मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री गृह सचिव, महामहिम राज्यपाल, प्रधानमंत्री तथा महामहिम राष्ट्रपति को प्रेषित निशान्त शर्मा की शिकायत प्रदेश के हर संवेदनशील नागरिक के लिये एक गंभीर चिन्ता का विषय बन गयी है। शिकायत के मुताबिक निशान्त शर्मा और उसके परिवार को दो व्यक्ति धर्मशाला स्थित मकलोडगंज में जान और माल की धमकी देते हैं। इस धमकी की शिकायत लेकर वह एस.पी. को मिलते हैं और मामला दर्ज करने का आग्रह करते हैं। इसी दिन डी.जी.पी. का फोन निशान्त शर्मा को आता है और उसे डी.जी.पी. से शिमला आकर मिलने की बात की जाती है। डी.जी.पी. के फोन आने के बाद उसी दिन निशान्त शर्मा को यह धमकी मिलने के बाद उसके साथ पूर्व में घटे कुछ वाक्यों को लेकर निशान्त शर्मा एस.पी. शिमला को एक तीन पन्नों की मेल भेजकर डी.जी.पी. के खिलाफ एफ.आई.आर. करने का आग्रह करते हैं। यह मेल साइट पर आने के बाद डी.जी.पी. निशान्त शर्मा के खिलाफ उन्हें बदनाम करने का आपराधिक मामला दर्ज करवा देते हैं। निशान्त के खिलाफ यह मामला दर्ज होने की जानकारी उसे दो पत्रकार देते हैं। जिनके मोबाइल नम्बर शिकायत में दर्ज हैं। शिकायत में निशान्त शर्मा उसके साथ 25 अगस्त को गुरुग्राम में घटी घटना की जानकारी देता है। इस संबंध में हरियाणा पुलिस के पास दर्ज करवाई गयी शिकायत और जांच में सी.सी.टी.वी. कैमरे की जांच में सामने आये तथ्यों की जानकारी भी अपनी शिकायत में हिमाचल पुलिस को भेजता है। इसमें कुछ लोगों के नाम भी लिखता है। लेकिन यह सामने होने के बाद भी हिमाचल पुलिस कोई मामला दर्ज नहीं करती है। इसी बीच उच्च न्यायालय इस सब का स्वतंत्र संज्ञान लेकर स्टेटस रिपोर्ट तलब करता है।

उच्च न्यायालय में जब स्टेटस रिपोर्ट आती है तब महाधिवक्ता डी.एस.पी. ज्वालामुखी के आश्वासन पर मामले में एफ.आई.आर. दर्ज कर लेने की प्रतिबद्धता अदालत को देते हैं। महाधिवक्ता की प्रतिबद्धता के बाद धर्मशाला पुलिस निशान्त की शिकायत पर कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है। निशान्त के आरोपों का बड़ा केन्द्र डी.जी.पी. है। यह सही है कि इस मामले की जांच से पहले डी.जी.पी. को किसी भी तरह से दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन जिस शिकायत के ज्यादा आरोप डी.जी.पी. के ही खिलाफ हो उस जांच की विश्वसनीयता स्थापित करने के लिये क्या किसी बाह्य एजेन्सी से जांच करवाना श्रेयस्कर नहीं होगा? क्योंकि जिस शिकायत में कुछ लोगों के सीधे नाम लिये गये हों क्या उसमें भी अनाम लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करना न्याय संगत हो सकता है? निश्चित है कि पुलिस की नजर में जब डी.जी.पी. का किसी भी तरह से इसमें शामिल होना नहीं पाया गया होगा तभी अनाम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया होगा। लेकिन क्या इससे सरकार की निष्पक्षता और जांच की विश्वसनीयता स्थापित हो पायेगी? यदि सरकार ने जांच के दौरान डी.जी.पी. को विभाग से अलग कर दिया होता या यह मामला सी.बी.आई. को सौंप दिया होता तो क्या इससे सभी की प्रतिष्ठा बहाल नहीं रहती? संभव है कि यह सारे सवाल आने वाले समय में अदालत के सामने भी उठें। क्योंकि डी.जी.पी. पर उठने वाले सवालों को तो विभाग अपनी प्रतिक्रिया में पहले ही सोशल मीडिया का प्रचार करार दे चुका है। डी.जी.पी. के अदालत में प्रतिवादी बनने या न बनने की स्टेज तो मामले का चलान दायर होने के बाद आयेगी।

- जब शिकायत में कई नाम है तो मामला अज्ञात लोगों के खिलाफ कैसे
- क्या सरकार यह जांच सी.बी.आई. को सौंपेगी या डी.जी.पी. को पद से हटाएगी
- इतने बड़े मामले पर विपक्ष की चुप्पी भी सवालों में

राज्यपाल ने भरमौर से 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आकांक्षी जिला चंबा के

जनजातीय उपमंडल मुख्यालय भरमौर में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत की पहचान आज सम्पूर्ण विश्व में एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में उभरी है। देश की नव-उन्नत प्रौद्योगिकी का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है।

शिव प्रताप शुक्ल ने इस दौरान 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि दो माह तक चलने वाली इस यात्रा का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी जनसाधारण तक पहुंचाना है।

राज्यपाल ने जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि विभिन्न योजनाओं का लाभ समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित बनाया जाए। उन्होंने लोगों से भी केंद्र सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं से जुड़कर इनसे लाभ उठाने का आहवान किया।

राज्यपाल ने प्रसिद्ध -ऐतिहासिक एवं धार्मिक 84 मंदिर परिसर में पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना भी की।

इंदिरा गांधी के दूरदर्शी निर्णयों का देश को हो रहा लाभः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐतिहासिक रिज पर भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री

इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में इंदिरा गांधी के योगदान को याद करते हुए कहा कि आज देश को उनके दूरदर्शी निर्णयों का लाभ मिल रहा है। उन्होंने आम आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए भू-सुधार कानून लाने और बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने जैसे साहसिक फैसले लिये। उन्होंने बांग्लादेश की मुक्ति में अहम योगदान दिया है, जो देशभक्ति का एक अद्वितीय उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा गांधी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया।

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, विधायक हरीश जनारथा, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, महापौर नगर निगम शिमला सुरेंद्र चौहान, पार्षदगण एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्यपाल ने महिला सशक्तिकरण के लिए समाज में बदलाव लाने पर दिया बल

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए समाज में परिवर्तन लाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि उन्हें समाज में उचित एवं समान अवसर प्रदान करने होंगे, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता से आगे बढ़ सकें।

राज्यपाल सुनील उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर सुनील उपाध्याय एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा 'महिला सशक्तिकरण -भारतीय परिप्रेक्ष्य' विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। शुक्ल ने कहा कि महिला सशक्तिकरण एक ऐसा विषय है जिस पर आज समाज और राष्ट्र को चर्चा करने और उचित ढंग से क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में महिलाओं को विशेष सम्मान प्राप्त था जो मध्यकाल में कम होने लगा। हालांकि आधुनिक युग में कई भारतीय महिलाएं महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक पदों पर आसीन हैं, लेकिन आम ग्रामीण महिलाएं अभी भी अपने घरों तक सीमित रहने के लिए मजबूर हैं।

राज्यपाल ने कहा कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की तुलना में शहरी क्षेत्रों की अधिक महिलाएं कामकाजी हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारतीय शहरों में लगभग 30 प्रतिशत महिलाएं सॉफ्टवेयर उद्योग में काम करती हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों में लगभग 90 प्रतिशत महिलाएं मुख्य रूप से कृषि और संबंधित क्षेत्रों में दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करती हैं। उन्होंने कहा कि हमारा देश तेजी से प्रगति कर रहा है, लेकिन हम इस गति को तभी बनाए रख सकते हैं, अगर हम लैंगिक असमानता को दूर कर सकें और महिलाओं के लिए पुरुषों के समान शिक्षा, पदोन्नति और वेतन सुनिश्चित कर सकें।

उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा लैंगिक असमानता और महिलाओं के विरूद्ध कुप्रथाओं को दूर करने के लिए कई संवैधानिक और कानूनी अधिकार बनाए और लागू किए गए हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

राज्यपाल ने कहा कि भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई अन्य योजनाएं संचालित की हैं इनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं मनरेगा, सर्वशिक्षा अभियान, जननी सुरक्षा योजना (मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए संचालित योजना) आदि हैं।

इस अवसर पर राज्यपाल ने समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया।

हमीरपुर में बिजली बोर्ड के मुख्य अभियन्ता का कार्यालय खोला जाएः सुरेश कुमार

शिमला/शैल। भोरंज के विधायक सुरेश कुमार ने मुख्यमंत्री

सुखविन्दर सिंह सुक्खू से उनके सरकारी आवास ओकओवर में भेंट की तथा उनका कुशलक्षेम जाना। उन्होंने मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र भी सौंपा जिसमें उन्होंने हमीरपुर में बिजली बोर्ड के मुख्य अभियन्ता का कार्यालय खोलने की मांग की।

सुरेश कुमार ने अवगत करवाया कि हमीरपुर के लोगों की यह चिरप्रतीक्षित मांग है क्योंकि बिजली बोर्ड के मुख्य अभियन्ता का कार्यालय वर्षों से मण्डी में कार्यरत है जिस कारण हमीरपुर के लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मण्डी में कार्यरत कार्यालय यथावत चलता रहे लेकिन हमीरपुर में मुख्य अभियन्ता का कार्यालय अलग से खोलना जनहित में रहेगा।

मुख्यमंत्री ने सुरेश कुमार के आग्रह को सुनने के पश्चात उन्हें शीघ्र ही उनकी मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया।

प्रदेश सरकार प्रोजेक्ट डवेल्पर कम्पनियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयासरतःजगत सिंह नेगी

शिमला/शैल। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए निवेशकों को अनुकूल सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। राज्य सरकार प्रदेश में स्थापित विभिन्न परियोजनाओं में शामिल प्रोजेक्ट डवेल्पर कम्पनियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयासरत है।

यहां प्रदेश में स्थापित विभिन्न परियोजनाओं में शामिल प्रोजेक्ट डवेल्पर कम्पनियों के साथ पटा राशि (लीज़ मनी) के संदर्भ में आयोजित बैठक के दौरान राजस्व मंत्री ने कहा कि विभिन्न प्रोजेक्ट डवेल्पर कम्पनियों ने अपना-अपना पक्ष रखा, जिस पर प्रदेश सरकार गहन विचार करेगी और लीज़ मनी से संबंधित मामलों को निपटाने का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश सरकार राज्य में निवेश करने वाली कम्पनियों को सभी सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ आवश्यक सहयोग भी प्रदान कर रही है।

उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को ऐसे सभी मामलों की सूची तैयार कर सभी कम्पनियों के साथ समन्वय स्थापित कर वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के बहुमूल्य संसाधनों का सदुपयोग कर विकास को गति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस अवसर पर प्रधान सचिव राजस्व ओंकार चन्द शर्मा, निदेशक ऊर्जा हरिकेश मीणा, विभिन्न प्रोजेक्ट डवेल्पर कम्पनियों के प्रतिनिधि, ऊर्जा तथा राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिये सांस्कृतिक दलों से आवेदन आमंत्रित

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों, योजनाओं व कार्यक्रमों का गीत-संगीत एवं नाटकों के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने के लिए निजी सांस्कृतिक दलों को दो वर्ष के लिए सूचीबद्ध किया जा रहा है। स्क्रीनिंग में प्रस्तुति के आधार पर उत्तीर्ण होने वाले सांस्कृतिक दलों को सूचीबद्ध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए हिमाचल प्रदेश सहकारिता अधिनियम के अधीन पंजीकृत सांस्कृतिक दल आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक निजी सांस्कृतिक दल में कम से कम चार महिला कलाकारों सहित कुल 11 कलाकार होने अनिवार्य हैं।

उन्होंने बताया कि प्रदेश के सांस्कृतिक दल अपना आवेदन निदेशालय, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हि.प्र., शिमला-171002 के कार्यालय में 04 दिसम्बर, 2023 तक जमा करवा सकते हैं। इस तिथि के उपरांत आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

आवेदनकर्ता सूचिबद्धता की शर्तें एवं आवेदन-पत्र को विभागीय वेबसाइट www.himachalpr.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादकःजे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

एशियन विकास बैंक के शिष्टमंडल ने बागवानी मंत्री से भेंट की

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी सिंचाई एवं मूल्य संवर्द्धन परियोजना (एच.पी.शिवा) के तहत एशियन विकास बैंक का एक शिष्टमंडल 14 से 21 नवम्बर, 2023 तक राज्य के आठ दिवसीय दौरे पर है।

शिष्टमंडल ने बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी से भेंट की तथा परियोजना से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। बागवानी मंत्री ने एशियन विकास बैंक की वित्तीय सहायता से एचपी शिवा परियोजना के तहत स्वच्छ पौध सामग्री, नर्सरी विकास, फसल कटाई उपरान्त प्रबन्धन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मजबूत करने पर बल दिया।

इसके उपरान्त सचिव बागवानी की अध्यक्षता में शिष्टमंडल के साथ एक बैठक आयोजित की गई। इसमें प्रदेश में लगभग 6000 हेक्टेयर में लागू की जाने वाली एचपीशिवा मुख्य परियोजना के कार्यान्वयन के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। इस परियोजना पर पांच वर्षों के लिए 130 मिलियन डॉलर का वित्तीय पोषण एशियन विकास बैंक द्वारा किया जाएगा।

शिष्टमंडल में टीम लीडर सुने किम, उप टीम लीडर कृष्ण रौतेला, अंतर्राष्ट्रीय बागवानी विशेषज्ञ श्याम खड़का, वित्त विशेषज्ञ जूलिटा पोन्नैया और तरूण अग्रवाल शामिल हैं।

भू-तापीय तकनीक से टापरी में स्थापित होगा 8 करोड़ रुपये का सीए प्लांट:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। आइसलैंड स्थित कंपनी जियोट्रॉपी आइसलैंड नवीन भू-तापीय (जियोथर्मल) प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पायलट आधार

पर किन्नौर जिले के टापरी में एक नियंत्रित वातावरण (सीए) स्टोर स्थापित करेगी, जिससे स्थानीय सेब उत्पादकों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में इस संबंध में राज्य सरकार और कंपनी के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया।

एचपीएमसी के प्रबंध निदेशक सुदेश कुमार मोख्टा ने राज्य सरकार की ओर से इस पर हस्ताक्षर किए, जबकि जियोट्रॉपी आइसलैंड के अध्यक्ष थॉमस ओटोहैन्सन ने कंपनी का प्रतिनिधित्व किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 8 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के इस सीए स्टोर की भंडारण क्षमता एक हजार टन होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस परियोजना को साकार करने के लिए कंपनी को हरसंभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि भू-तापीय ऊर्जा एक नवीकरणीय स्रोत है जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करता है। यह पर्यावरण को संरक्षित करने के राज्य सरकार के लक्ष्य के अनुरूप है तथा भू-तापीय प्रौद्योगिकी को अपनाना कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में भी उपयोगी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रदेश का पहला भू-तापीय प्रौद्योगिकी आधारित सीए स्टोर एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरा हो जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में सतलुज घाटी क्षेत्र में और भी भू-तापीय प्रौद्योगिकी आधारित सीए स्टोर स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने राज्य में बिजली उत्पादन के लिए भी आधुनिक युग की इस तकनीक का उपयोग करने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए।

कंपनी के अध्यक्ष थॉमस ओटोहैन्सन ने भंडारण सुविधा के लिए भू-तापीय प्रौद्योगिकी को नियोजित करने के लाभों को रेखांकित किया और परियोजना से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान की।

इस अवसर पर उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कृषि मंत्री चंद्र कुमार, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, भारत में आइसलैंड के राजदूत गुओनी ब्रैगसन, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव भरत खेड़ा, प्रधान सचिव आरडी नाजिम व अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

पुलिस विभाग में 1200 कांसटेबल और महिला सब इंस्पेक्टर की होगी भर्ती:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप पुलिस विभाग में सुधारों पर बल दिया है। गृह विभाग के

वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि बदलती तकनीक के साथ-साथ अपराध के तौर-तरीकों में भी बदलाव आया है। इसे देखते हुए पुलिस विभाग को अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव लाना आवश्यक है। इसके दृष्टिगत आधुनिक तकनीक अपनाने के साथ ही पेशेवर दृष्टिकोण में सुधार जरूरी है। उन्होंने पुलिस विभाग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा अन्य आधुनिक सॉफ्टवेयर के उपयोग के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकार पर्याप्त धन उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में पुलिस विभाग में 1200 से अधिक कांसटेबल और महिला सब-इंस्पेक्टर की भर्ती की जाएगी।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आधुनिक प्रौद्योगिकी में सिद्धस्त पुलिस कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान कर उनका एक पूल तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे विभिन्न अभियानों में उनका प्रभावी योगदान सुनिश्चित हो सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक थाने में पुलिस कर्मी साइबर क्राइम से निपटने में भी सक्षम होने चाहिए। उन्होंने प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठों एवं मंदिरों इत्यादि में आयोजित होने वाले मेलों के दौरान बेहतर पुलिस व्यवस्था के लिए पुलिस अधीक्षक के पास आरक्षित बल रखने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने आबादी, क्षेत्रफल, अपराध दर, पर्यटकों की संख्या सहित अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के पुलिस थानों की पुनःसंरचना करने के निर्देश दिए, ताकि वहां स्थानीय जरूरतों व इन कारकों के आधार पर पुलिसकर्मी तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा सकें। उन्होंने थानों को श्रेणीबद्ध करने और पुलिस चौकियों के स्थान पर केवल पुलिस थाने ही खोलने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश भी दिए, ताकि कानून-व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके। उन्होंने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती के लिए रोटेशन नीति बनाने, संवेदनशील पदों पर केवल तीन वर्ष तक ही तैनाती करने और इसके उपरान्त अनिवार्य तौर पर उन्हें कूलिंग ऑफ पीरियड देने के निर्देश दिए, ताकि पुलिस के कामकाज में जबावदेही सुनिश्चित की जा सके।

मुख्यमंत्री ने शिक्षण संस्थानों के समीप नशीले पदार्थों (ड्रग्स) की समस्या की रोकथाम के लिए विशेष टीमें तैनात करने के निर्देश भी दिए, ताकि बच्चों को नशे जैसी बुराई से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में फील्ड गतिविधियों के लिए पैट्रोल व डीजल वाहन तथा स्टाफ के लिए ई-वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे। पुलिस अधीक्षक कार्यालय नूरपुर को सुदृढ़ करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि यहां पर पर्याप्त पुलिस कर्मी तैनात करने के साथ ही आधारभूत ढांचा भी सुदृढ़ किया जाएगा।

बैठक में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, सचिव गृह डॉ. अभिषेक जैन, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (गृह रक्षक) राकेश अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सीआईडी) सतवंत अटवाल, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) अभिषेक त्रिवेदी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (जेल) ए.पी. सिंह उपस्थित थे।

लम्बित राजस्व मामलों का 20 जनवरी तक निपटारा सुनिश्चित करें:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंतकाल, तकसीम तथा निशानदेही के लम्बित मामलों का 20 जनवरी 2024 तक निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी ने प्रदेश में लम्बित राजस्व मामलों की समीक्षा की और सभी उपायुक्तों को मिशन मोड पर लम्बित मामलों का निपटारा करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार आमजन की सरकार है तथा जन समस्याओं का निपटारा हमारी प्राथमिकता है, इसलिए सरकार लम्बित राजस्व मामलों की संख्या शून्य करना चाहती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में काफी संख्या में राजस्व मामले लम्बित हैं, जिनका तुरंत निपटारा करना आवश्यक है तथा सभी अधिकारी इस मामले पर गंभीरता से पर कार्रवाई करें।

उन्होंने कहा कि नायब तहसीलदार से लेकर मंडलीय आयुक्त लम्बित राजस्व मामलों की दैनिक आधार पर सुनवाई कर उनका समयबद्ध निपटारा करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों की वार्षिक एसीआर में भी इस प्रगति को दर्शाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश भर में 30 व 31 अक्तूबर, 2023 को इंतकाल अदालतों का आयोजन किया, जिसके परिणाम बेहतर रहे तथा इंतकाल के लम्बित 41,907 मामलों में से 31,105 का निपटारा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आगामी 1 व 2 दिसंबर को पुनः प्रदेश भर में इस प्रकार की विशेष अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसे राजस्व लोक अदालत का नाम दिया गया है। इस विशेष अदालत में इंतकाल के साथ-साथ तकसीम के लम्बित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाएगा।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी उपायुक्तों को निपटाये गये मामलों की पूरी रिपोर्ट मासिक आधार पर भेजने के निर्देश दिए, जिसमें व्यक्ति का नाम, पता और फोन नम्बर का पूरा विवरण उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि उपायुक्त अपने-अपने जिलों में राजस्व अधिकारियों के साथ बैठकें कर लंबित राजस्व मामलों का तेजी से निपटारा करने की रणनीति तैयार करें। इसके लिए आवश्यकता अनुसार स्टाफ का युक्तिकरण करें। उन्होंने कहा कि किसी भी राजस्व मामले में तीन दिन से अधिक की तिथि न दी जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने राजस्व कानून में संशोधन किया है तथा अब सम्मन की सर्विस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जिलों में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार उपायुक्तों को सेवानिवृत्त कानूनगो की सेवाएं लेने की अनुमति भी देगी। उन्होंने मुख्य सचिव को मंडलीय आयुक्तों के स्तर पर लम्बित राजस्व मामलों की निरंतर समीक्षा करने के निर्देश दिए और कहा कि राजस्व मंत्री 20 जनवरी से पहले पूरे प्रदेश में इस मामले की प्रगति की समीक्षा करें।

बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, प्रधान सचिव आरडी नजीम शिमला में उपस्थित रहे, जबकि सभी उपायुक्त और मंडलीय आयुक्त वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

प्रदेश में 31 अक्तूबर 2023 तक तकसीम के लम्बित मामलों का जिला वार ब्योरा यह है। बिलासपुर 1407, चंबा 680, हमीरपुर 2413, कांगड़ा 12,014, किन्नौर 156, कुल्लू 1057, लाहौल-स्पीति 48, मंडी 3208, शिमला 1288, सिरमौर 1072, सोलन 1156, ऊना 3973

मुख्यमंत्री ने दिए सौर ऊर्जा स्थापित करने की योजना की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की और प्रदेश में सौर ऊर्जा योजनाओं की रूपरेखा जल्द से जल्द तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने 100 किलोवाट से लेकर एक मेगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना पर युवाओं को 40 प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की है तथा विभाग इस योजना को जल्द से जल्द अमलीजामा पहनाने के दृष्टिगत इसकी रूपरेखा शीघ्र तैयार करे।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस योजना से जहां हिमाचली युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, वहीं हिमाचल को हरित राज्य बनाने के वर्तमान राज्य सरकार के प्रयासों को भी इससे बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल को 31 मार्च, 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि यहां के पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके। राज्य सरकार सौर ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से स्थापित इकाइयों से 25 वर्ष के लिए बिजली की खरीद करेगी, जिससे युवाओं को आय के स्थाई स्रोत प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा इकाइयां स्थापित करने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत राज्य सरकार 40 प्रतिशत सब्सिडी भी प्रदान कर रही है।

उन्होंने कहा, 'नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति राज्य सरकार का यह सक्रिय दृष्टिकोण न केवल पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देगा, बल्कि विकास और रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा, जिससे हिमाचल देश में स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में अग्रणी बनेगा।'

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सौर ऊर्जा के दोहन को बढ़ावा दे रही है और वर्ष 2023-24 में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इस दिशा में अनेकों कदम उठाये जा रहे हैं और वर्तमान राज्य सरकार ने अपना पहला बजट भी हरित बजट के रूप में प्रस्तुत किया है।

बैठक में मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, प्रबंध निदेशक हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड हरिकेश मीणा, हिमऊर्जा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शुभ करण सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

आकांक्षा, अज्ञानता और असमानता – यह बंधन की त्रिमूर्तियां हैं। ..... स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

प्रशासनिक ट्रिब्यूनल क्या वक्त की जरूरत है

हिमाचल सरकार ने प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को फिर से बहाल करने का निर्णय लिया है क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनावों में ऐसा आश्वासन प्रदेश के कर्मचारियों को दिया गया था। प्रदेश में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की स्थापना 1986 में की गयी थी। 1986 के बाद इसे दो बार बन्द किया गया। संयोगवश बन्द करने का फैसला दोनों बार भाजपा शासन के दौरान ही लिया गया। जुलाई 2019 में पूर्व जयराम ठाकुर की सरकार के दौरान कर्मचारियों के ही आग्रह पर लिया गया था। आज इसे दोबारा खोलने का फैसला क्या इसलिये लिया जा रहा है कि बन्द करने का फैसला पूर्व सरकार ने लिया था। 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने प्रदेश की जनता को दस गारंटीयां भी दी थी। लाखों युवाओं को रोजगार देने का वायदा भी किया गया था। लेकिन जब इन गारंटीयों को पूरा करने की बात आयी तब प्रदेश के सामने राज्य की कठिन वित्तीय स्थिति का राग अलाप कर श्रीलंका जैसे हालात होने की चेतावनी दे डाली। इसके बाद प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र लाकर 92 हजार करोड़ की देनदारी विरासत में मिलने की बात कर दी। इस कर्ज की विरासत के नाम पर कितनी बार कितनी सेवाओं और वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि कर दी गई है यह सिर्फ उपभोक्ता ही जानता है। इस कठिन वितिय स्थिति के नाम पर ही सरकार ने अब तक 12000 करोड़ का कर्ज ले लिया है। जो स्थितियां आज प्रदेश की चल रही है उनके मध्य नजर यह स्पष्ट है कि सरकार आम जनता से किया गया कोई भी वायदा पूरा नहीं कर पायेगी। क्योंकि सरकार भ्रष्टाचार से लगातार समझौता करती जा रही है। बल्कि भ्रष्टाचार अब सरकार के एजैन्डे पर ही नहीं है। इस परिदृश्य में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल दोबारा खोलकर प्रदेश पर सौ करोड़ का बोझ डालना कितना हितकारी होगा यह आम सवाल बन गया है। जब जुलाई 2019 में ट्रिब्यूनल को बन्द कर दिया गया था और कर्मचारी मामले प्रदेश उच्च न्यायालय को ट्रांसफर कर दिये गये थे तब इन मामलों के आंकड़ों पर ही उच्च न्यायालय से न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ौतरी की गयी थी। मुख्य न्यायालय में जजों की संख्या 13 से 17 कर दी गयी थी। अब फिर इस संख्या को 17 से 21 करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। अब जब ट्रिब्यूनल फिर से खोल दिया जायेगा तो कर्मचारियों के मामले वहां से ट्रांसफर होकर ट्रिब्यूनल में वापस आएंगे और इसका असर उच्च न्यायालय पर पड़ेगा और उसके विस्तार का रास्ता रुक जायेगा। दूसरी ओर ट्रिब्यूनल के लिये एक अलग भवन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्योंकि पुराना भवन अब उच्च न्यायालय के पास नहीं है। ऐसे में यह अहम सवाल हो जाता है कि क्या कर्ज लेकर ऐसी व्यवस्था करना आवश्यक है। इस समय कर्मचारियों के कई मामले लंबित पड़े हुये हैं। 2016 में जो वेतनमानों में संशोधन हुआ था उसके मुताबिक सरकार अभी तक सरकारी कर्मचारियों को भुगतान नहीं कर पायी हो सेवानिवृत कर्मचारी इन लाभों के लिये उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं। दर्जनों मामलों पर उच्च न्यायालय कर्मचारियों को यह भुगतान 6% ब्याज सहित करने के आदेश कर चुका है लेकिन सरकार इन फसलों पर अमल नहीं कर पा रही है। ऐसी करोडों की देनदारियां सरकार के नाम खड़ी हो गयी है और कर्मचारियों में रोष फैलता जा रहा है। इस वस्तुस्थिति में ट्रिब्यूनल की बहाली कुछ सेवानिवृत्ति बड़े अधिकारियों के पुन: रोजगार का साधन बनने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर पायेगा। बल्कि कर्मचारियों को जो न्याय आज तक उच्च न्यायालय से मिल रहा है उसके मिलने का रास्ता भी लम्बा हो जायेगा। यह ट्रिब्यूनल पुन: खोलने से पहले सरकार को यह आंकड़ा जारी करना चाहिये की जब यह संस्थान खोला गया था तब कितने मामले इसके पास आये थे। प्रतिवर्ष औसतन कितने मामलों का फैसला हुआ है। उच्च न्यायालय में कर्मचारियों के कितने मामले प्रतिवर्ष निपटाये गये? आज इसे खोलने की आवश्यकता क्यों आयी है? इस पर प्रतिवर्ष कितना खर्च होगा और उसका साधन क्या होगा। सरकार जब तक तार्किक तरीके से अपना पक्ष जनता में नहीं रखेगी तब तक इस प्रयास को कर्ज लेकर घी पीने का जुगाड़ ही माना जायेगा।

पहले हमास के खिलाफ निंदा प्रस्ताव तो पारित करें, फिर इजरायल का भी विरोध कर लें

गौतम चौधरी

इस्लामिक चरमपंथी संगठन हमास के खिलाफ इजरायल की सैन्य कारवाई को लेकर भारत का राजनीतिक खेमा, साफ तौर पर दो भागों में विभाजित दिख रहा है। जहां एक ओर सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी के नेता इजरायल का समर्थन करते दिख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वामदल सहित कई इस्लामी रूझान की पार्टियों ने फिलिस्तीन के बहाने हमास के प्रति हमदर्दी दिखाई है। इधर कांग्रेस इस मुद्दे पर भी मध्यम मार्ग को ही चुना है। हालांकि भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि हमास एक आतंकवादी संगठन है और फिलिस्तीन की आम जनता पर इजरायल की सैन्य कारवाई किसी कीमत पर उचित नहीं है।

इस पूरे प्रकरण में अभी तक भारत सरकार से लेकर किसी भी राजनीतिक पार्टियों ने हमास के खिलाफ खुले तौर पर निंदा प्रस्ताव पारित नहीं किया है, जबकि भारत के कुछ मुस्लिम संगठनों ने हमास के समर्थन में रैलियां निकाली है। यहां तक कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी या फिर सरकार ने भी हमास के खिलाफ कड़े शब्दों में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। इससे पुरातनपंथी इस्लामिक ताकतों को बल मिलेगा, जो एक बार फिर भारत को इस्लामिक आतंकवाद के जद में लाकर खड़ा कर सकता है।

बता दें कि भारत किसी भी प्रकार के आतंकवाद का विरोध करता रहा है। यह भारतीय विदेश नीति का अंग है। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी कई बार कई मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। बावजूद इसके हमास द्वारा इजरायल के आम लोगों पर किये गये हमले की निंदा भारत सरकार ने नहीं की है। यह कहीं न कहीं भारत में पनप रहे इस्लामिक चरमपंथियों को बल प्रदान कर रहा है। यही नहीं इस मामले में कांग्रेस का मौन भी बेहद खतरनाक है। सबसे ज्यादा खतरनाक तो वामदलों के द्वारा फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां निकालना है। नि:संदेह फिलिस्तीन में इजरायल जो कर रहा है वह अमानवीय है लेकिन हमास ने जो किया उसे किस तर्क से सही ठहराया जा सकता है? जो लोग फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां निकाल रहे हैं, उन्हें उन्हीं रैलियों में सबसे पहले हमास की निंदा करनी चाहिए फिर इजरायल के खिलाफ भाषण प्रारंभ करना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बिना हमास की निंदा किये रैलियां हो रही है। इससे भारत के अंदर पल रहे इस्लामिक चरमपंथियों में गलत संदेश जा रहा है, जो न तो भारतीय राष्ट्रवाद के हित में है और न ही देश के लोकतांत्रिक ढ़ाचे को सूट करता है।

इस मामले में वामदल की तुलना में भूमिगत वाम संगठनों की सोच ज्यादा सकारात्मक और परिपक्व दिख रहा है। उन्होंने नि:संदेह फिलिस्तीन का समर्थन किया है लेकिन हमास की कृत्य पर भी वे संजीदा हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि वे फिलिस्तीनी जनता के साथ हैं लेकिन हमास के द्वारा आम इजरायलियों पर किया गया हमला कतई उचित नहीं है।

भारत विगत लंबे समय से इस्लामिक आतंकवाद की जद में रहा है। यहां कई आतंकी हमले हो चुके हैं। यहां तक कि भारतीय लोकतंत्र के हृदय स्थल संसद भवन पर भी इस्लामिक आतंकवादी हमला कर चुके हैं। ऐसे में भारत के राजनेताओं या फिर बुद्धिजीवियों को ऐसा कोई भी मौका नहीं देना चाहिए जिससे इस्लामिक चरमपंथी मजबूत हों और पाकिस्तान व ईरान की तरह देश की सत्ता को अपनी उंगलियों पर नचाये।

यहां इस बात का जिक्र कर दें कि वर्ष 1924 में जब तुर्की के खलीफा को बर्तानियां सल्तनत के द्वारा अपदस्त किया गया तो विश्वव्यापी खिलाफत आन्दोलन प्रारंभ हुआ। उस आन्दोलन में भारतीय मुसलमानों ने भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। अपने तात्कालिक राष्ट्रीय हितों को देखते हुए भारत के कुछ स्वतंत्रता सैनानियों ने भी उस इस्लामिक आन्दोलन का समर्थन किया था। यह सच है कि भारत के विभाजन के लिए कई अन्य कारक भी जिम्मेदार थे लेकिन बिना कुछ सोचे समझे खिलाफत आन्दोलन में भारतीय नेताओं का कूद जाना भी देश के विभाजन का एक प्रमुख कारण बना। दो राष्ट्र के सिद्धांत पर पाकिस्तान बनाने की इस्लामिक पुरातन पंथियों का साथ देने वाले आज न तो पश्चिमी पाकिस्तान में दिख रहे हैं और न ही बांग्लादेश में उनका कोई नामोनिशान बचा है। इसलिए क्षणिक राजनीतिक लाभ के लिए फिलिस्तीन के बहाने हमास का समर्थन ठीक नहीं है।

इजरायल-फिलिस्तीन युद्ध को लेकर दुनिया का हर मुल्क अपने-अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रख, अपनी रणनीति बनायी है। यहां तक कि मुस्लिम देशों ने भी खुले तौर पर हमास का समर्थन नहीं किया है। कई इस्लामिक देशों ने तो हमास की निंदा भी की है। ऐसे में हमे भी अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर संवेदनशील होना चाहिए। इस युद्ध को लेकर भारत सरकार ने जो रणनीति अपनाई है वह हमारे देश के लिये हितकर है। वहीं इस देश के हर एक राजनीतिक दल और राजनेता की रणनीति होनी चाहिए। इस मामले में हमारी सरकार को भी थोड़ा कठोर होना पड़ेगा। उसे हमास के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करना चाहिए। साथ ही इजरायल द्वारा आम फिलिस्तीनियों पर अमानवीय हमलों का खुलकर विरोध करना चाहिए।

हिमाचल प्रदेश क्षेत्र के जनजातीय जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा ने रफ्तार पकड़ी

पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में लॉन्च की तैयारियां तेज

केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पूरे देश में पहुंचाने के उद्देश्य से एक अभूतपूर्व पहल के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा के पहले चरण में हिमाचल प्रदेश के तीन जनजातीय जिलों अर्थात चंबा, स्पीति और किन्नौर को कवर किया जा रहा है, जो इसकी पहुंच के महत्वपूर्ण विस्तार का प्रतीक है।

पंजाब और हरियाणा के लिए यात्रा 22 नवंबर को शुरू होने वाली है।

विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रयास देश की लगभग हर ग्राम पंचायत को कवर करना है। इसके तहत पंजाब में 13,646 स्थानों को कवर किया जाएगा, जबकि हरियाणा में यह यात्रा 6,537 स्थानों तक पहुंचेगी और हिमाचल प्रदेश में 3,799 स्थानों को लक्षित किया गया है।

तत्काल सेवाओं को सुगम बनाने के लिए, डाक विभाग, स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों द्वारा विभिन्न शिविर लगाये जाएंगे। सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में नागरिकों को सूचित करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए आरंभ की गई इस यात्रा का उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाना है।

जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सरकारी योजनाओं के संदेश देने वाली विशेष रूप से डिजाइन की गई आईईसी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वैनों को स्थानीय भाषाओं में सूचना सामग्री से सज्जित किया गया है, और ये ऑडियो-विजुअल, ब्रोशर, पैम्फलेट, बुकलेट और स्टैंडीज़ के माध्यम से जानकारी का प्रसार करेंगी। फोकस क्षेत्रों में स्वच्छता, वित्तीय सेवाएं, बिजली, एलपीजी कनेक्शन, आवास, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छ पानी आदि शामिल हैं।

लाभार्थियों के साथ बातचीत, उपलब्धियों का जश्न, ऑन-द-स्पष्ट क्विज़ प्रतियोगिताएं, ड्रोन प्रदर्शन, स्वास्थ्य शिविर और मेरा युवा भारत स्वयंसेवक नामांकन सहित जन भागीदारी कार्यक्रम जमीनी गतिविधियों का अभिन्न अंग बनेंगे।

सबसे बड़ी आउटरीच पहलों में से एक विकसित भारत अभियान का लक्ष्य 25 जनवरी, 2024 तक 2.55 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों और 3,600 शहरी स्थानीय निकायों को कवर करना है। 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण के साथ संचालित यह व्यापक अभियान राज्य सरकारों, जिला प्राधिकरणों, शहरी स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है।

एआई अपने साथ अपनी तरह की चुनौतियां और नैतिक सवाल लायी है

पत्रकारों और मीडिया पेशेवरों के लिए सत्य के सिद्धांतों के प्रति व्यापक प्रतिबद्धता दर्शानी आवश्यक:उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़

एआई समाचारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन वह अनुभवी समाचार संपादकों की जगह नहीं ले सकती:अनुराग ठाकुर

कुछ पश्चिमी पूर्वाग्रहों द्वारा प्रचारित मिथ्या धारणाओं को दूर करना महत्वपूर्ण है:ठाकुर

शिमला। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर मीडिया जगत को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। भारतीय प्रेस परिषद द्वारा 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के दौर में मीडिया' विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में ठाकुर ने कहा कि आज जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि का दिन है। उन्होंने कहा कि अब से कुछ ही वर्षों में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, इसलिए उन्हें आशा है कि मीडिया केवल भारत के परिवर्तन की कहानी को ही नहीं, बल्कि उसके विभिन्न सूबों और क्षेत्रों के अरबों लोगों की आशाओं, आकांक्षाओं पर भी प्रकाश डालने में तेजी से रचनात्मक भूमिका निभाएगा।

आज के दिन के महत्व को रेखांकित करते हुए ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए समर्पित पत्रकारों की अथक प्रतिबद्धता का सम्मान करता है।

कार्यक्रम के विषय पर अपने विचार रखते हुए ठाकुर ने कहा कि 'हम इतिहास में एक ऐसे महत्वपूर्ण दौर में हैं, जो उन्नत प्रौद्योगिकी द्वारा त्वरित गति से संचालित वैश्विक विकास का साक्षी बन रहा है। डिजिटल युग ने एक नए युग का सूत्रपात किया है, जहां समाचार सामग्री तैयार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का तेजी से उपयोग किया जा रहा है। यद्यपि एआई समाचार रिपोर्टिंग में निस्संदेह एक नया आयाम जोड़ती है, लेकिन इसकी सीमाओं को पहचानना भी महत्वपूर्ण है। 'समाचार जुटाने और समाचार प्रसार के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती सावधानी बरतना और मीडिया में एआई का जिम्मेदार उपयोग सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।

ठाकुर ने कुछ पश्चिमी संस्थाओं द्वारा उत्पन्न की जा रही नकारात्मक धारणा की पड़ताल करते हुए कहा कि भले ही हम प्रेस की स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, लेकिन हम उन लोगों को नजरअंदाज नहीं सकते, जो हमारे राष्ट्र की भावना को कमजोर करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति और मीडिया आउटलेट हैं, जो भारत के खिलाफ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार मिथ्या प्रचार करते हैं। ऐसी धारणाओं को चुनौती देना, झूठ उजागर करना और सत्य की जीत सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि भारत के चित्रण और उसके मीडिया के संबंध में कुछ पश्चिमी पूर्वाग्रहों द्वारा लगातार प्रचारित की जा रही गलत धारणाओं को दूर करना महत्वपूर्ण है। औपनिवेशिक खुमारी अक्सर धारणाओं को विकृत कर देती है, लेकिन हम दावा करते हैं कि हमारा मीडिया परिदृश्य गतिशील, चिंतनशील है और अपने गुणों पर आधारित है। भारत का मीडिया इसकी सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतिबिंब है, और हमें वैश्विक विमर्श में इसके योगदानों पर गर्व करना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत अपने यहां जीवंत और स्वतंत्र प्रेस का दावा करता है, जो विविध मतों और विचारों के लिए मंच प्रदान करती है।

ठाकुर ने कई अन्य व्यवसायों के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में प्रवेश कर चुके मीडिया को आगाह करते हुए कहा कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां एक बटन दबाकर गलत सूचना को बढ़ा-चढ़ाकर फैलाया जा सकता है। हमारी सरकार मीडिया को एक विवेकशील दृष्टिकोण अपनाने, सनसनी फैलाने के नुकसान से बचने और हमारे समाज के ताने-बाने को नुकसान पहुंचाने वाली धारणाओं से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय मीडिया को हमारे राष्ट्र के हितों की रक्षा करनी चाहिए और हमारी प्रिय एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले भारत विरोधी विचारों को स्थान देने से बचना चाहिए।

केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने यह सुनिश्चित करने के लिए भारतीय प्रेस परिषद की भूमिका की सराहना की कि प्रेस निष्पक्ष एवं जिम्मेदार तरीके से पत्रकारीय नैतिकता व मानकों का पालन करते हुए राष्ट्र की सेवा में अपनी भूमिका निभाए। उन्होंने मीडिया से भीतर और बाहर दोनों जगह हो रहे बदलावों को लगातार अपनाने का आह्वान किया। डॉ. मुरुगन ने कॉपीराइट, रचनात्मकता, मौलिकता और साहित्यिक चोरी के मामलों में एआई के अतिक्रमण के प्रति आगाह किया। उन्होंने कहा कि किसी भी अन्य तकनीक की तरह, एआई को भी नैतिक मानवीय निगरानी की आवश्यकता है।

इससे पहले, इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्य अतिथि, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि फर्जी खबरें, जानबूझकर गलत और शरारतपूर्ण जानकारी, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और प्राथमिकताएं, सत्ता की पक्षधरता की प्रवृत्ति और आर्थिक लालच ने आज मीडिया के प्रति लोगों का भरोसा घटा दिया है। उन्होंने कहा कि आज मीडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती विश्वसनीयता की है और आश्चर्य की बात यह है कि इस पहलू को बड़े आनंदपूर्वक नजरअंदाज किया जा रहा है।

कार्यक्रम के विषय के बारे में अपने विचार रखते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगमन ने हमारे समाचार, सूचना और मनोरंजन को प्राप्त करने तथा उसका उपयोग करने के तरीके को बदल दिया है। एआई हमारे रोजमर्रा के जीवन का अभिन्न अंग बन गयी है। साथ ही, यह अपने साथ अपनी तरह की चुनौतियां और नैतिक सवाल लायी है, जैसे कि गलत सूचना का प्रसार, डीप फेक, इको चैंबर का सृजन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने तथा समाज में अराजकता और अस्थिरता पैदा करने के लिए सूचना की माइक्रो टार्गेटिंग। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों का सामना करते हुए, पत्रकारों और मीडिया पेशेवरों की ज़िम्मेदारियां बढ़ गई हैं, जिससे सच्चाई, सटीकता और जवाबदेही के सिद्धांतों के प्रति और भी अधिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है।

धनखड़ ने कहा कि यद्यपि एआई में नुकसान पहुंचाने की क्षमता है, लेकिन हमें यह स्वीकार करना होगा कि यह तकनीक यहां रहेगी और हमें बदलते परिदृश्य के अनुरूप ढलना होगा, अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए एआई की परिवर्तनकारी क्षमता को एक उपकरण के रूप में नियोजित करना होगा, साथ ही इसके दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा भी प्रदान करनी होगी। उन्होंने कहा, 'यह सर्वोपरि है कि पत्रकार और मीडिया आउटलेट ईमानदारी के उच्चतम मानकों को बनाए रखें। तथ्य-जांच, स्रोत का सत्यापन और संपादकीय स्वतंत्रता बनाए रखना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो चुका है। हमें एआई को उन मूल्यों से समझौता नहीं करने देना चाहिए जो स्वतंत्र और जीवंत प्रेस की बुनियाद हैं। धनखड़ ने रेखांकित किया कि एआई भले ही एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है, लेकिन यह मानवीय स्पर्श, सत्य के लिए प्रतिबद्धता और पत्रकारों का अटूट समर्पण है जो मीडिया को हमारे समाज में अच्छाई के लिए ताकत बनाता रहेगा।

इस अवसर पर जी-20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि मीडिया संस्थाएं जो तकनीक को विकल्प के रूप में न देखकर, मानवीय प्रतिभा को बढ़ाने वाले साधन के रूप में देखती हैं, वे खोजी और दस्तावेजी पत्रकारिता को फिर से जीवंत करने में सक्षम रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि अनूठी कहानियों से लैस एआई द्वारा तैयार ऑडियो और वीडियो कहानी कहने की सभी सीमाओं को अभूतपूर्व रूप से तोड़ देंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया में एआई के अनियंत्रित उपयोग से हमारे लोकतंत्र को होने वाले नुकसान के बारे में सजग रहना आवश्यक है। एआई की सहायता से वैयक्तिकृत समाचारों को क्यूरेट करना हमारे समाज में विविध दृष्टिकोणों तक हमारे संपर्क को सीमित करने वाले इको चैंबर का निर्माण करने का जोखिम उत्पन्न करता है।

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने की।

'आपातकाल के दौरान वैकल्पिक संचार' के लिए एमेच्योर और सामुदायिक रेडियो को बढ़ावा देने की योजना

बुनियादी हैम उपकरणों की लागत पर प्रदान किया जाएगा 60 हजार रुपये उपदान

शिमला। प्राकृतिक आपदा की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश अति संवेदनशील क्षेत्रों में शामिल है। भूकंप, बाढ़ अथवा भू-स्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रभावित क्षेत्रों की संचार प्रणाली भी प्रभावित होती है, जिससे राहत एवं बचाव कार्यों में भी अनावश्यक देरी हो जाती है। इन्हीं बाधाओं से पार पाने तथा संचार प्रणाली को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा शौकिया रेडियो को बढ़ावा देने की योजना तैयार की गई है।

हिमाचल प्रदेश में दूर-दराज के ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां आमतौर पर मानसून, बर्फबारी या किसी भी विपरीत मौसम में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अन्य क्षेत्र से संपर्क कट जाते हैं। ऐसे कई ब्लैकआउट जोन भी राज्य में हैं, जहां संचार की सुलभ सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। ऐसे क्षेत्रों में प्रभावी आपातकालीन संचार चैनल के वैकल्पिक माध्यम विकसित करने की आवश्यकता अरसे से महसूस की जाती रही है। संकट और आपदाओं के समय में, जब वायरलाइन, सेल फोन और संचार के अन्य पारंपरिक साधन विफल हो जाते हैं, तो शौकिया रेडियो का उपयोग अक्सर आपातकालीन संचार के साधन के रूप में किया जाता है।

आपदा के दौरान प्रभावित क्षेत्र की संचार प्रणाली को सबसे पहले क्षति होती है। प्राकृतिक आपदा के कारण, आपदा की तीव्रता के आधार पर संचार प्रणाली को आंशिक क्षति या फिर संपूर्ण संचार नेटवर्क से संबंधित बुनियादी ढांचा पूरी तरह प्रभावित हो सकता है। सबसे खराब स्थिति में, पूरा संचार नेटवर्क टूट सकता है। ऐसे में जिला और राज्य प्रतिक्रिया प्रणाली को जान-माल के नुकसान सहित राहत एवं बचाव कार्यों की प्रगति के बारे में जानने में समस्याएं आती हैं।

इसी को ध्यान में रखते हुए, प्रदेश सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत एक योजना तैयार की गई है। 'आपातकाल के दौरान वैकल्पिक संचार' के दृष्टिगत तैयार इस योजना के तहत प्राधिकरण द्वारा शौकिया (हैम) और सामुदायिक रेडियो के माध्यम से आपात स्थिति और आपदाओं के लिए संचार के वैकल्पिक साधनों को बढ़ावा दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि एमेच्योर रेडियो के माध्यम से एक वायरलेस संचार नेटवर्क, संचार के सबसे प्रभावी और वैकल्पिक माध्यमों में से एक है। प्रशिक्षित शौकिया रेडियो ऑपरेटर के कौशल का उपयोग जरूरत और आपात स्थिति के समय सार्वजनिक सेवा के लिए किया जा सकता है।

इस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के तहत इच्छुक स्वयंसेवक अथवा अधिकारी को आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। हैम रेडियो में इच्छुक स्वयंसेवकों अथवा सरकारी अधिकारियों व गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जायेगा। हैम ऑपरेटरों के लिए राज्य में परीक्षा आयोजित की जायेगी तथा निःशुल्क पंजीकरण तथा लाइसेंसिंग सहायता प्रदान की जायेगी। लाइसेंस परीक्षा में उत्तीर्ण सभी व्यक्तियों को बुनियादी हैम उपकरणों की लागत में 60,000 रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। हैम रेडियो को बढ़ावा देने के लिए राज्य में शिक्षा संस्थानों में हैम रेडियो क्लब की स्थापना की जायेगी।

इच्छुक व्यक्ति https://forms.gle/D4QXR5vnPuQ5GjZo8 ऑनलाइन लिंक पर आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के उपरान्त इसे भर कर अपने नजदीकी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अथवा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिये ट्रेनिंग एवं कैपेसिटी बिल्डिंग समन्वयक, डीएम-सेल, राजस्व विभाग से भी संपर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मोबाइल नंबर 94183-53814, टेलीफोन 0177- 2621154 तथा ईमेल sdmahp @nic.in पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

780 मेगावाट जंगी थोपन पोवारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के आवंटन को रद्द करने का निर्णय

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यपाल से हिमाचल प्रदेश विधानसभा

का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से 23 दिसंबर 2023 तक तपोवन धर्मशाला में आयोजित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में जल शक्ति विभाग में 4500 पैरा-कर्मचारियों को नियुक्त करने, राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग में कर एवं कराधान निरीक्षक के 25 पद और बागवानी विभाग में बागवानी विकास अधिकारी के 10 पद भरने का भी निर्णय लिया गया।

बैठक में मोटर वाहन कर की एकमुश्त छूट के साथ-साथ पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) में स्क्रैप किए जाने वाले पुराने वाहनों से संबंधित ब्याज और जुर्माने की एकमुश्त छूट को भी स्वीकृति प्रदान की गई। यह छूट एक वर्ष की समयावधि के लिए लागू होगी, जो वाहन मालिकों को मौजूदा नियमों के अनुरूप अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए पर्यावरण अनुकूल दृष्टि से जिम्मेदार विकल्प चुनने के लिए प्रेरित करेगी। इसके अतिरिक्त वैध सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट प्रस्तुत करने पर नए वाहन के पंजीकरण के लिए हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम-1972 की धारा 14 के तहत देय कर पर गैर परिवहन वाहनों को 15 वर्ष तक 25 प्रतिशत और परिवहन वाहनों के मामले में आठ वर्ष तक 15 प्रतिशत रियायत देने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने एसजेवीएनएल के पक्ष में किए गए जंगी थोपन पोवारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट (780 मेगावाट) के आवंटन को रद्द करने का निर्णय भी लिया। कंपनी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर परियोजना के कार्यान्वयन में प्रगति में विफलता पर यह निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने शिमला, चौपाल तथा कुल्लू के और अधिक क्षेत्रों को योजना क्षेत्र के अंतर्गत लाने की स्वीकृति प्रदान की ताकि इन क्षेत्रों में असुरक्षित निर्माण कार्यों पर रोक लगाई जा सके। प्रदेश में कार्यरत सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश सहकारी समितियां नियम, 1971 में संशोधन करने को भी मंजूरी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त प्रदेश के मंदिरों में संग्रहित सोने, चांदी का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए हिमाचल प्रदेश हिंदू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती नियम, 1984 के नियमों में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया।

बैठक में शैक्षणिक सत्र 2024-25 से प्रदेश के सभी स्कूलों में पहली कक्षा में प्रवेश पाने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए छह वर्ष से अधिक आयु का मानदंड अपनाने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 10000 रुपये मासिक किराया देने की भी कार्योत्तर स्वकृति प्रदान की गई।

खेल अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए ब्रिटेन से मांगा सहयोग

शिमला/शैल। ब्रिटिश उप-उच्चायुक्त कैरोलिन रोवेट ने लोक निर्माण, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह से भेंट की।

इस अवसर पर आपसी सहयोग के विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई।

बैठक में विशेष तौर पर प्रदेश में खेल ढांचे के सुदृढ़ीकरण एवं खिलाड़ियों के प्रशिक्षण आदान-प्रदान कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। इसके तहत हिमाचल एवं ब्रिटेन के मध्य मैत्री मैच आयोजित करने पर भी चर्चा की गई। इससे सांस्कृतिक आदान-प्रदान के साथ ही क्षमता विकास और संबंधों को मज़बूत करने में भी सहायता मिल सकेगी। हिमाचल ने खेल ढांचे के उन्नयन एवं इसमें निवेश, विभिन्न खेलों से जुड़े कोचों को आधुनिक कोचिंग, खिलाड़ियों के ऑनलाइन तथा ऑफलाइन कोचिंग, खेल मनोविज्ञान से संबंधित कोर्स एवं एक स्थायी संयुक्त समिति के गठन का भी आग्रह किया। इसके अतिरिक्त विभिन्न गतिविधियों के लिए निधि, प्रशासनिक आदान-प्रदान कार्यक्रम, खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता में वृद्धि के दृष्टिगत अनुकूलन पाठयक्रम तथा हाई एल्टीटयूड प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने में सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई।

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान प्रदेश सरकार ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने ब्रिटिश उप-उच्चायुक्त से प्रदेश में खेल अधोसंरचना को सुदृढ़ करने में हर संभव सहयोग का आग्रह किया।

बैठक में हाल ही में भारी बरसात के कारण प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से भूधंसाव व भूस्खलन के कारण सड़कों व पुलों को हुई क्षति तथा प्रदेश सरकार व विभाग द्वारा जारी पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास कार्यों पर भी चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री ने ई-चार्जिंग स्टेशन पर 10 दिन में मांगी रिपोर्ट

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में विभाग से ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के संबंध में 10 दिन के भीतर वस्तु-स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-वाहनों के संचालन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में 107 ई-चार्जिंग स्टेशन का निर्माण प्रस्तावित है, जिनमें से 53 ई-चार्जिंग स्टेशन विभिन्न पेट्रोल पंपों पर तथा 54 का निर्माण परिवहन विभाग के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में विभाग उन्हें विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में प्रस्तावित 6 हरित गलियारों (ग्रीन कोरिडोर) के निर्माण कार्य की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने परवाणू-नालागढ़-ऊना-हमीरपुर-संसारपुर टेरेस, पांवटा-नाहन-सोलन-शिमला, परवाणु-सोलन-शिमला-रामपुर-लोसर, मंडी-जोगिंदरनगर-पालमपुर-धर्मशाला-कांगड़ा-पठानकोट और कीरतपुर-बिलासपुर-मंडी-मनाली-केलंग-जिंगजिंगबार ग्रीन कोरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने इन हरित गलियारों पर बिजली ट्रासंफॉर्मर लगाने तथा निर्माण संबंधी टेंडर प्रक्रिया की जानकारी भी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि चरणबद्ध तरीके से हिमाचल पथ परिवहन निगम की डीजल बसों को ई-बसों के साथ बदला जाएगा तथा जल्द ही 300 नई ई-बसों की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निगम को घाटे से उबारने के लिए प्रयासरत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत ई-वाहनों के संचालन को प्राथमिकता प्रदान कर रही है तथा सरकारी विभागों में भी ई-टैक्सी संबद्ध की जाएंगी। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों युवाओं को स्वरोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिए उनसे ई-टैक्सी किराए पर ली जाएंगी, जिन्हें सरकारी विभागों में तैनात किया जाएगा। ई-टैक्सी के पंजीकरण के लिए एक वैबसाइट तैयार की जा रही है, जिसका जल्द ही शुभारंभ किया जाएगा।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार युवाओं को स्वरोज़गार प्रदान करने लिए 680 करोड़ रुपये की एक स्टार्ट-अप योजना का प्रथम चरण जल्द ही शुरू करने जा रही है। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग अब रोज़गार प्रदाताओं का भी पंजीकरण कर रही है ताकि उन्हें उनकी आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षित युवा मिल सकें।

बैठक में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव आर.डी. नजीम, सचिव गृह डॉ. अभिषेक जैन, हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर, श्रम आयुक्त मानसी सहाय ठाकुर, निदेशक डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस मुकेश रेप्सवाल, निदेशक परिवहन अनुपम कश्यप सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

हिमाचली हथकरघा उत्पादों के व्यापार में ब्रिटेन से सहयोग पर चर्चा

शिमला/शैल। चण्डीगढ़ स्थित ब्रिटिश उप- उच्चायुक्त कैरोलिन रोवेट के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने यहां उद्योग, आयुष व संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान से भेंट की। इस दौरान हिमाचल एवं ब्रिटेन के मध्य व्यापार

निवेश के प्रोत्साहन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई।

हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि बैठक में विशेष तौर पर हथकरघा उद्योग से संबंधित चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में हिमाचल के समान मौसम एवं जलवायु के दृष्टिगत वहां प्रदेश में तैयार हथकरघा उत्पादों के लिए बेहतर बाजार विकसित हो सकता है। उन्होंने इस संदर्भ में उप-उच्चायुक्त से ब्रिटेन में एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भेजने में सहयोग का आग्रह किया गया। इस प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों के साथ ही भुटिको जैसे प्रीमियम ब्रांड से जुड़े सदस्य शामिल किए जा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कुल्लू में स्थित आरआरएग्रो लिमिटेड को भूमि आवंटन की दिशा में आगे बढ़ रही है। उनके उत्पादों की ब्रिटेन में भारी मांग है और वहां की एक कम्पनी भी कुल्लू में नई विनिर्माण इकाई स्थापित करने में निवेश कर रही है। इससे क्षेत्र में रोज़गार के अतिरिक्त अवसर भी सृजित हो सकेंगे।

उन्होंने कहा कि शराब एवं वाइन क्षेत्र में भी प्रदेश विदेशी निवेश आमंत्रित कर रहा है। राज्य सरकार ने हाल ही में स्कॉटलैंड की एक कम्पनी इयान मैकलियोड की 50.80 करोड़ रुपये की निवेश वाली एक परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। इससे 77 लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। कम्पनी को ऊना जिला के औद्योगिक क्षेत्र पंडोगा में अत्याधुनिक माल्ट डिस्टीलरी प्लांट स्थापित करने के लिए नवम्बर, 2021 में 43,700 वर्गमीटर भूमि भी आवंटित की गई है। कम्पनी द्वारा इस प्लांट की स्थापना के लिए अभी तक लगभग 40 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है।

बैठक में ब्रिटिश उप-उच्चायुक्त चंडीगढ़ के समन्वय से अगले वर्ष भारत एवं इंग्लैंड के मध्य धर्मशाला में प्रस्तावित क्रिकेट टेस्ट मैच के दौरान एक फैशन शो से संबंधित आयोजन की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। इससे हिमाचली हथकरघा उत्पादों एवं यहां की संस्कृति को प्रोत्साहन मिल सकेगा।

एचपी शिवा को सफल बनाने के लिए बेहतर समन्वय के साथ कार्य करें सम्बद्ध विभाग:जगत सिंह नेगी

शिमला/शैल। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में जल शक्ति तथा बागवानी विभाग के साथ हिमाचल प्रदेश उपोष्णकटिबंधीय बागवानी सिंचाई एवं मूल्य संवर्धन परियोजना (एचपी शिवा) की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

जगत सिंह नेगी ने कहा कि एचपी शिवा बागवानी क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण परियोजना है, जिससे प्रदेश में अभूतपूर्व विकास सुनिश्चित होगा। परियोजना को सफल बनाने के लिए सम्बद्ध विभागों को बेहतर तालमेल के साथ कार्य करना चाहिए। परियोजना के तहत किए जा रहे विभिन्न कार्यों की समय-समय पर निगरानी की जाए जिससे यह परियोजना समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित हो सके।

उन्होंने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों से परियोजना के तहत कार्यान्वित की जा रही विभिन्न सिंचाई योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इन सभी योजनाओं को समय पर पूरा किया जाए।

बागवानी मंत्री ने एशियन विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित एचपी शिवा परियोजना को जमीनी तौर पर सफल बनाने के लिए विभाग के अधिकारियों को फील्ड में जाकर हितधारकों की समस्याएं जानने तथा उनका समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य राज्य में चलाई जा रही योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना है ताकि इनका लाभ समय पर पात्र लाभार्थियों को मिल सके।

इस अवसर पर सचिव बागवानी सी.पालरासू, निदेशक बागवानी संदीप कदम, प्रबन्धा निदेशक एचपीएमसी सुदेश कुमार मोख्टा, परियोजना निदेशक एचपी शिवा देवेन्द्र ठाकुर, जल शक्ति तथा बागवानी विभाग अधिकारी भी उपस्थित थे।

लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में आज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा प्रेस:मुकेश अग्निहोत्री

प्राकृतिक आपदा के दौरान मीडिया की भूमिका रही सराहनीय:संजय अवस्थी

शिमला/शैल। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर 'कृत्रिम मेधा के दौर में मीडिया की भूमिका' विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता की और मीडिया जगत से जुड़े लोगों को इस दिवस पर बधाई दी।

उन्होंने कहा कि पत्रकार महत्त्वपूर्ण सामाजिक घटनाओं, सरकार के काम से सम्बंधित जानकारी और अन्य सूचनाओं को सच्चाई और तथ्य के आधार पर समाज के समक्ष प्रस्तुत करने का दायित्व निभाते हैं। उन्होंने कहा कि खबरों से ही एक पत्रकार की पहचान होती है और पाठकों के बीच पत्रकार की विश्वसनियता ही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है।

उन्होंने कहा कि पत्रकारिता में सत्यता, वस्तुनिष्ठा, पारदर्शिता और निष्पक्षता की अपेक्षा रहती है। पिछले दो दशकों में पत्रकारिता के क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन का प्रभाव साफ देखा जा सकता है। आधुनिक युग में सूचनाओं का आदान-प्रदान बहुत तेजी से हो रहा है। इसमें सोशल मीडिया की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। समय के साथ पत्रकारिता के तरीकों में भी बदलाव देखने को मिला है और मीडिया में आज नयी तकनीकें अपनायी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रिंट मीडिया और ब्रॉडकास्ट मीडिया के साथ ही आज सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन हर माध्यम की अपनी एक महत्ता है जो कभी कम नहीं होगी।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने भी नवीन प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को अपने विभागों में शामिल करने की पहल की है। इसी का परिणाम है कि आज सरकारी क्षेत्र के सभी विभाग ई-ऑफिस से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा सड़क सुरक्षा, अपराध नियंत्रण, पुलिस विभाग व शिक्षा आदि क्षेत्रों में सरकार नवीनतम प्रौद्योगिकी व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से उल्लेखनीय कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार से आज प्रत्येक व्यक्ति सूचना सम्प्रेषण का एक माध्यम बन चुका है। हाल ही की प्राकृतिक आपदा में हुए नुकसान से संबंधित विभिन्न वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से आम लोगों द्वारा ही प्रसारित किए गए।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रेस लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में आज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सरकार व जनता के मध्य संवाद

कायम करने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने आहवान किया कि वर्तमान प्रदेश सरकार के विकासात्मक कार्यक्रमों एवं कल्याणकारी योजनाओं को प्रदेश के लोगों तक पहुंचाने में अपनी सार्थक भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि परिवहन निगम की बसों में न्यूनतम शुल्क पर सामान भेजने की सुविधा, वाहनों के नम्बरों की ऑनलाइन नीलामी और चिंतपूर्णी मंदिर में वीआईपी दर्शन की सुविधा जैसी नवोन्मेषी पहलों से प्रदेश के राजस्व में करोड़ों रुपयों की वृद्धि होने के साथ ही पारदर्शिता भी बढ़ी है। ऐसे निर्णयों के सकारात्मक पहलुओं को सही परिप्रेक्ष्य में लोगों तक पहुंचाने में मीडिया की भूमिका सराहनीय रही है।

मुख्य संसदीय सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क, संजय अवस्थी ने कहा कि आजादी से लेकर वर्तमान तक मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। परिवर्तन के इस दौर को आत्मसात करते हुए हमें अपने मूल्यों एवं आदर्शों पर ही अडिग रहना होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर आयोजित परिचर्चा हमें सामयिक मुद्दों पर विमर्श का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान मीडिया की भूमिका सराहनीय रही है।

परिचर्चा में भाग लेते हुए मुख्य वक्ता द ट्रिब्यून चण्डीगढ़ के एसोसिएट सम्पादक संजीव बरयाना ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्सानियत का भविष्य है। इससे हमारा कार्य आसान हुआ है और समाचारों के प्रसार में भी तेजी आयी है। उन्होंने एआई के सचेत उपयोग पर बल देते हुए कहा कि इसके शरारतपूर्ण अथवा गलत उपयोग से व्यापक स्तर पर हानि से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से वस्तुनिष्ठता तो संभव है, लेकिन यह चेतना के स्तर पर कभी भी व्यक्तिनिष्ठ नहीं हो सकती। उन्होंने डीपफेक जैसे माध्यमों से हाल ही में वीडियो से छेड़छाड़ कर तथ्यहीन सूचनाओं के प्रसार से संबंधित उदाहरण भी प्रस्तुत किए।

दैनिक जागरण के हिमाचल संस्करण के सम्पादक नवनीत शर्मा ने कहा कि हमें कृत्रिम मेधा को शत्रु समझने के बजाये सहायक समझना चाहिए। हालांकि एआई को विवेक के अनुसार हम कैसे अपनाते हैं, यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि मानवीय संवेदना के स्तर पर कृत्रिम मेधा इन्सान के सामने कहीं नहीं ठहरती। यह एक ऐसा दोस्त है, जो आपसे हाथ मिला सकता है, गले लग सकता है, लेकिन आगोश में नहीं समा सकता। उन्होंने कहा कि आभासी दुनिया में 90 के दशक के अन्तिम वर्षों में कृत्रि मेधा का उपयोग आरम्भ हो गया था। मीडिया जगत को भी इसका सचेत उपयोग करना उनके दैनिक कार्यों में सहायक होगा।

पंजाब केसरी डिजिटल टीवी के सम्पादक संजीव शर्मा ने कहा कि बदलते दौर के साथ सूचना प्रौद्योगिकी भी निरंतर उन्नत होती गई है। आरम्भ में बदलाव से हमें संकोच होता है और निरन्तर उपयोग से हम इसके प्रति सहज महसूस करने लगते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से घबराने अथवा डरने की आवश्यकता नहीं है। अपितु इसके सकारात्मक पहलुओं को अपनाते हुए हमें इनके उपयोग पर संकोच नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के दौर में एआई का उपयोग आवश्यक है मगर तथ्यों की जांच-परख भी उतना ही जरूरी है।

इससे पूर्व, निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क राजीव कुमार ने विभाग की ओर से सभी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में त्वरित बदलाव से सूचनाओं के आदान-प्रदान के माध्यमों में भी व्यापक वृद्धि हुई है। इससे पत्रकारिता में भी विविधता आयी है।

परिचर्चा में विभिन्न मीडिया प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार साझा किए।

इस अवसर पर स्थानीय विधायक हरीश जनारथा, नगर निगम शिमला के महापौर सुरेन्द्र चौहान, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग की अतिरिक्त निदेशक आरती गुप्ता, संयुक्त निदेशक प्रदीप कंवर एवं महेश पठानिया सहित अन्य विभागीय अधिकारी व शिमला स्थित विभिन्न मीडिया संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 में हिमाचली उत्पादों की धूम

शिमला/शैल। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में हिमाचल के उत्पादों की बिक्री में वृद्धि दर्ज की जा रही है। 14 से 27 नवम्बर तक आयोजित इस ट्रेड फेयर में हिमाचल मंडप स्थापित किया गया है जिसका उद्घाटन आवासीय आयुक्त मीरा मोहंती द्वारा किया गया। मंडल में 14 स्टॉल स्थापित किए गए हैं। इनमें विशुद्ध हिमाचली उत्पाद बिक्री के लिए रखे गये हैं। विशेष तौर पर हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पाद, फल उत्पाद के अलावा कांगड़ा चाय, सीबकथोर्न इत्यादि लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। आगन्तुक सिरमौर ज़िले के मैसर्ज डिलमन डेलिकेसी द्वारा तैयार चीड़ की पत्तियों पर आधारित लीवर डेटॉक्स व अन्य उत्पादों के प्रति भी खासी रूचि दिखा रहे हैं। इन उत्पादों को बढ़ते प्रदूषण से शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कम करने में कारगर माना जा रहा है। हिमाचली उत्पादों के लिए विदेशों से भी आपूर्ति आदेश प्राप्त हो रहे हैं।

उद्योग विभाग के संयुक्त निदेशक व हिमाचल पैवेलियन के निदेशक ज्ञान सिंह चौहान ने बताया कि विभाग द्वारा अपने कैंप ऑफिस में इन उत्पादों की बिजनेस नेटवर्किंग की भी सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।

अंतरराष्ट्रीय लवी मेले में जाइका के लिबास पर फिदा हुए सैलानी

शिमला/शैल। अंतरराष्ट्रीय लवी मेले के दौरान जाइका वानिकी परियोजना के तहत निर्मित लिबास पर आम व्यक्ति और सैलानी खूब फिदा हुए। मेले के दौरान जाइका के स्टॉल में किन्नौरी एवं पारंपरिक लिबास की जमकर बिक्री हुई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक चार दिनों के इस मेले में जाइका के तहत स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री लाखों में हुई। प्रदेश के विभिन्न जिलों से यहां पहुंचे लोगों ने किन्नौरी पटी से निर्मित कोट, चोली, बास्केट समेत जैकेट की खूब खरीददारी की। यानी कुल मिलाकर कम दाम में क्वालिटी प्रोडक्ट्स खरीद कर लोग काफी खुश दिखे। उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय लवी मेले के अवसर पर 11 से 14 नवंबर तक जाइका वानिकी परियोजना के स्टॉल में लगे उत्पादों की जमकर सराहना भी हुई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक यहां किन्नौरी टोपी 400 रुपये प्रति, लेडीज बास्केट 1600, जेंट्स बास्केट 1800, किन्नैरी चोली 2500 और किन्नौरी पटी वाला कोट मात्र 4500 रुपये में उपलब्ध हैं। इसके अलावा लोकल लसन के आचार, लोकल शहद, ढिंगरी मशरूम, किन्नौरी दाक, किन्नौरी राजमाह, सूखा पुदीना, कोदे का आटा, चुल्ली का तेल, सूखा बरांश की बिक्री हुई। जाइका के तहत विभिन्न स्वयं सहायता समूहों की ओर से निर्मित इन उत्पादों लवी मेले में तहलका मचा दिया। मेले के समापन्न अवसर पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी जाइका प्रोजेक्ट के तहत निर्मित सभी उत्पादों की सराहना की। उन्होंने जाइका वानिकी परियोजना के तहत विभिन्न सहायता समूहों को बधाई भी दी। बताया गया कि स्वयं सहायता समूह रामपुर डिविजन की सेल 41915, स्वयं सहायता समूह आनी डिविजन की सेल 188435 और किन्नौर फोरेस्ट डिविजन के तहत स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री 137270 रुपये की हुई। सभी स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों ने जाइको वानिकी परियोजना के मुख्य परियोजना निदेशक नागेश कुमार गुलेरिया का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आज नागेश कुमार गुलेरिया के सहयोग से स्वरोजगार एवं आजीविका कमाने का बेहतर अवसर मिल रहा है।

अंतरराष्ट्रीय लवी मेला रामपुर में इस बार चिलगोजे के मांग सबसे अधिक रही। यहां जाइका की ओर से लगे स्टॉल में हर तरह के आर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मांग अधिक रही। मक्की का आटा, सूखे मटर, फाफरा, ओगला, चुल्ली का तेल, शहद, चिलगोजा और ड्राई मशरूम की भी खूब बिक्री हुई। बताया गया कि फोरेस्ट सर्कल रामपुर के 12 सहायता समूहों के उत्पादों पर हर कोई फिदा होते दिखे। रामपुर और किन्नौर डिविजन के 3-3 और आनी डिविजन के 6 सहायता समूहों के उत्पादों की मांग हर रोज होती रही।

ब्यास बेसिन में 131 स्टोन क्रशरों में से 68 के पास नहीं पाई गई अनुमति

शिमला/शैल। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में हाल ही की बरसात में आई प्राकृतिक आपदा के उपरान्त गठित मल्टी सेक्टर कमेटी ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसमें आपदा के लिए जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ अवैज्ञानिक और अवैध खनन को प्रमुख कारक पाया गया है।

कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ब्यास नदी बेसिन पर 131 स्टोन क्रशर स्थापित हैं, जिनमें से 68 के पास इनके संचालन के लिए जरूरी अनुमति नहीं पायी गयी तथा 50 संचालकों के पास ही जरूरी अनुमति पायी गयी है। इसके अतिरिक्त 7 क्रशर बाढ़ से प्रभावित पाये गये जबकि 6 में भण्डारण से संबंधित तथा अन्य अनियमितताएं पायी गयी हैं। इसके साथ-साथ नदी में अत्याधिक मलबा फैंकने के कारण बाढ़ ने गंभीर रूप धारण किया, जिससे आस-पास के सामुदायिक ढांचे और जान माल को भारी नुकसान पहुंचा। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ब्यास नदी का पर्यावरणीय संतुलन भारी दबाव में है, जिसका वैज्ञानिक अध्ययन करने की आवश्यकता है तथा स्टोन क्रशरों के संचालन के लिए लघु, मध्यम तथा दीर्घावधि उपाय सुझाने पर भी बल दिया गया है।

उन्होंने कहा कि समिति ने जरूरी अनुमति प्राप्त 50 स्टोन क्रशर को कुछ शर्तों के साथ संचालित करने की अनुमति प्रदान करने की सिफारिश की है, जिसके तहत यह क्रशर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 12 घंटे के लिए संचालित किए जा सकते हैं। समिति ने सिफारिश की है कि किसी भी क्रशर पर डीजी सेट का प्रयोग अवैध बनाया जाना चाहिए। भविष्य में सभी स्टोन क्रशरों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की भी सिफारिश की गई है, जिनकी निगरानी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा खनन विभाग के अधिकारी करें। स्टोन क्रशर के 500 मीटर दायरे में अगर कोई भी गैर-कानूनी खनन पाया गया तो स्थानीय अधिकारी लिखित में रिपोर्ट दें, अन्यथा उसी स्टोन क्रशर पर कारवाई की जाये। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जिन स्टोन क्रशर के पास जरूरी अनुमतियां नहीं हैं, उन्हें पहले यह अनुमतियां प्राप्त करनी होंगी, जिसके बाद मामला दर मामला आधार पर उन्हें खोलने पर विचार किया जाये।

प्रवक्ता ने कहा कि समिति ने यह भी सिफारिश की है कि प्रदेश के पर्यावरणीय संतुलन के लिये राज्य सरकार खनन व स्टोन क्रशरों के संचालन की अनुमति, नवीनीकरण आदि भविष्य में एक खिड़की आधार पर उच्च स्तरीय अधिकृत समिति के माध्यम से प्रदान की जायें। समिति की अंतिम रिपोर्ट आने तक प्रदेश में नये स्टोन क्रशर खोलने पर अस्थाई प्रतिबंध रहे। रिपोर्ट में कैप्टिव स्टोन क्रशर के संचालन की प्रक्रिया को भी सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया गया है ताकि उनका उपयोग गैरकानूनी गतिविधियों में न हो सके।

प्रवक्ता ने कहा कि उद्योग विभाग समिति की सिफारिशों का अध्ययन कर रहा है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

दोपहर को लिये जा रहे फैसले शाम तक बदलने पड़ रहे

- क्या सरकार में आपसी तालमेल का अभाव है?
- क्या वित्तीय दबाव के कारण अव्यवहारिक फैसले लिये जा रहे हैं?

शिमला/शैल। नेता प्रतिपक्ष

पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर आरोप लगाया है कि इसमें आपसी तालमेल का गंभीर अभाव है। क्योंकि सरकार द्वारा दोपहर को लिये फैसले शाम को ही बदल दिये जा रहे हैं। जय राम ठाकुर ने यह आरोप तब लगाया जब सरकार ने शनिवार को दोपहर में यह अधिसूचना जारी की पटवारी और कानूनगो अब से राज्य सरकार के कर्मचारी होंगे। यह अधिसूचना आने पर संबधित कर्मचारियों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं देनी शुरू कर दी। लेकिन थोड़ी देर बाद दूसरी अधिसूचना आ गयी और इसमें पहले को खारिज कर दिया गया। इससे पहले परिवहन निगम लग्गेज पॉलिसी लायी और बुजुर्गो की दवाई से लेकर बच्चों के खेलने के समान पर भी किराया वसूला। विशेष पथकर लगाकर प्रदेश की पर्यटन को तबाह कर दिया। जब जनता में रोष पनपा तो इन फैसलों को भी बदलना पड़ा। स्टोन क्रेशर बंद करने और फिर खोलने का फैसला भी सोच विचार के अभाव को ही दिखता है। माध्यमिक शिक्षा में पहले गेस्ट शिक्षक योजना की बातें की गयी और बाद में उसे बदल दिया गया।

इस तरह फैसले लेने और उन पर अमल से पहले ही उन्हें बदल देना यही दिखता है कि बिना व्यापक विचार विमर्श के फैसले लिये जा रहे हैं। सरकार में आपस में तालमेल का गहरा संकट चल रहा है। इस तरह की कार्य प्रणाली का आम जनता पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ऐसे बिना सोच विचार लिये जा रहे फैसलों से जनता में यही संदेश जा रहा है कि सरकार पैसा इकट्ठा करने के लिये कोई भी फैसला ले रही है। लेकिन फैसलों की यह व्यवहारिकता नहीं देखी जा रही है कि उनका आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज सरकार हरित ऊर्जा के नाम ई-वाहन खरीद योजना पर 50% तक अनुदान देने की घोषणा कर रही है। लेकिन इस घोषणा के बाद भी लोग आगे नहीं आ रहे हैं। इससे यह स्पष्ट संकेत जाता है कि लोग इस योजना की पहाड़ी क्षेत्र में सफलता को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। फिर आज प्रदेश जिस तरह के वित्तीय संकट में चल रहा है उसमें यह सवाल और भी अहम हो जाता है कि क्या कर्ज लेकर ऐसी योजनाओं को लाना आवश्यक है।

विकसित भारत संकल्प यात्रा के हिमाचल में चलेंगे 90 रथ

प्रदेश और केंद्र सरकार की सभी योजनाओं की संपूर्ण जानकारी रथ में रहेगी उपलब्ध

शिमला/शैल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने कहा विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा पिछले 9 वर्षो के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की योजनाएं समाज कल्याण, गरीब कल्याण और समस्त समाज के उत्थान के लिए चलाई गई।

यह केंद्र सरकार की एक व्यंगम यात्रा पूरे देश में प्रारंभ की गई है, 15 नवंबर को झारखंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा का श्रीगणेश किया। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी यह यात्रा प्रारंभ हो चुकी है जिसके प्रथम चरण में हिमाचल प्रदेश में जनजातीय क्षेत्र में यह यात्रा अभी चल रही है।

बिंदल ने कहा की इस यात्रा का उद्देश्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, हमारे गांव-गांव में यह रथ पहुंचेंगे। इसमें केंद्र और प्रदेश सरकार की संपूर्ण जानकारियां रहेगी। गरीबों के लिए, माताओं बहनों के लिए, रोजगार संबंधित कौन सी योजनाएं हैं, महिला मंडलों के लिए कौन सी योजनाएं हैं, स्वास्थ्य संबंधित और जो योजनाएं केंद्र की सरकार द्वारा चलाई जा रही की जानकारियां आम जनमानस को प्राप्त करवाई जायेगी, ताकि प्रत्येक व्यक्ति उन योजनाओं का लाभ ले सके।

हिमाचल प्रदेश में इस यात्रा में 90 गाड़ियां प्रदेश की योजनाओं की जानकारी लेकर के चलने वाली है। हिमाचल के जनजातीय क्षेत्रों में यह गाड़ियां चल चुकी है और 25 नवंबर से शेष हिमाचल के अंदर भी यह रथ चलने शुरू हो जाएंगे।

इन रथों में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की संपूर्ण जानकारी पत्र और पुस्तकों के माध्यम से जन जन तक पहुचाई जायेगी। इन रथों के अंदर कुछ वीडियो रील उपलब्ध रहेगी जो की इनमें दिखाई जाएगी, जिससे बहुत सारी जानकारियां भी लोगों को प्राप्त होगी।

इसमें सभी मोबाइल एप्स की जानकारी होगी, जिसको हम अपने मोबाइल पर डाउनलोड करके सभी योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं।

हिमाचल प्रदेश की सभी योजनाओं की जानकारी भी हमें वहां से प्राप्त हो सकती है।

उन्होंने कहा कि यह यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे जितने लोगों को हम जोड़ेंगे उतनी जल्दी हम गरीब कल्याण योजनाओं को धरातल पर पहुंचा सकेंगे, इस यात्रा में सभी लोगों को बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए।

अरनी विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या हुई दो हजार

शिमला/शैल। अरनी विश्वविद्यालय के चांसलर विवेक

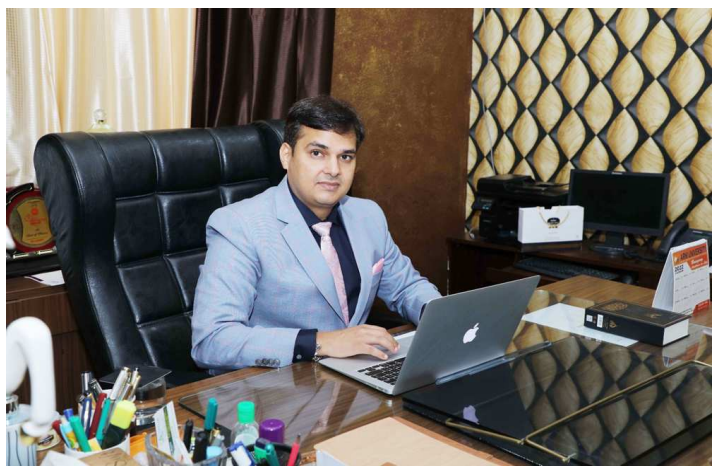

सिंह उच्च शिक्षा को एक नया आयाम प्रदान कर रहे हैं यह दावा किया है अरनी विश्वविद्यालय ने एक प्रेस ब्यान में। इस विश्वविद्यालय को 2009 में यूजीसी की मान्यता प्राप्त हुई थी और तब यहां पर विद्यार्थियों की संख्या केवल 200 थी जो आज बढ़कर 2023 में 2000 तक पहुंच गयी है। इस समय में प्रदेश में निजी क्षेत्र में खुले कुछ विश्वविद्यालय बन्द होने की कगार पर पहुंच गये हैं। उच्च शिक्षा नियामक आयोग कई विश्वविद्यालयों को अपने निरीक्षण के बाद जुर्माना तक लगा चुका है। बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने कोविड के कारण उस दौरान विद्यार्थियों की संख्या कम होने का तर्क दिया है और उसका प्रभाव अब तक चले आने की बात की है। ऐसे में यदि किसी विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है तो यह स्वत: प्रमाणित हो जाता है कि वह अपने समकक्षों से कुछ तो बेहतर सेवाएं प्रदान कर रहा होगा। यूजीसी के मानकों की अनुपालना न होने के कोई आरोप इस विश्वविद्यालय के खिलाफ अब तक सामने नहीं आये हैं। इसका श्रेय विश्वविद्यालय के चांसलर को दिया जा रहा है। दावा किया गया है कि कुलपति विवेक सिंह एक दशक पहले यहां आये थे उन्होंने विश्वविद्यालय में नए शिक्षण तकनीकों साफ्ट स्किल्ज और आधुनिक पाठयक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया और विश्वविद्यालय को उत्तर भारत में विद्यार्थियों के आकर्षण का केंद्र बना दिया। यहां आधुनिक युग के पाठयक्रम प्रस्तुत किये जा रहे हैं जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साईस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे विकसित होने वाले क्षेत्र शामिल हैं। जो विद्यार्थियों को तेजी से बढ़ते जॉब मार्केट के लिये तैयार करते हैं। विश्वविद्यालय इन्टर डिविजनरी लर्निंग को बढ़ावा देता है जिससे छात्रों को व्यक्तित्व विकास में बढ़ावा मिलता है। विश्वविद्यालय के इस प्रसार का श्रेय चांसलर विवेक सिंह को दिया जा रहा है।